



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार 6 अगस्त, 1991/15 श्रावण, 1913

हिमाचल एवेश सरकार

कायनिय अतिरिक्त उपायकृत, कांगड़ा स्थित धर्मधाला

कारण वताश्वो नोटिस

धर्मशाला-176215, 29 जून, 1991

संडां 1826-27.—झेयोंका ग्राम पंचायत चकवन्धींग के अंकेक्षण अवधि 6-8-80 से 15-1-90 में निम्न पंचायत निधि के दृश्ययोग/छलहरण के मालाले सालों द्वाये हैं:—

(1) प्रधान पंचायत लगातार वर्ष 1980 से अब तक हजारों में पंचायत निधि अपने पास अनाधिकृत रूप से रखकर पंचायत को क्षति पहुंचाते रहे हैं। उसका उल्लेख अंकेश्वण पव के पृष्ठ 18 से 20 में है। 1/90 की भी प्रधान के पास मु0 5155.30 रुपये नकद शेष के रूप में थे। जब आपको दिनांक 10-4-91 को नकद शेष की राशि जमा करने के लिये कहा तो आपने बताया कि आपने भवत किया कि मामला अदालत में चला है। नकद शेष की अदायगी पर रोक लगाई गई है। अदालत में चल रहे विवाद की पुष्टि में प्रतिलिपि 17-4-1991 तक जिला पंचायत अधिकारी को उपलब्ध करवाने का विश्वास दिया था परन्तु आज तक प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि आप वास्तविकता को छुपा कर पंचायत निधि का निरन्तर दुश्ययोग कर रहे हैं।

(2) मीन प्रिंटिंग प्रेस, कांगड़ा से 454/- रुपये लेखन सामग्री का क्रय दिखाकर पंचायत रिकाई में न स्टाक की वस्तुओं का इन्द्राज पाया गया और प्रयाणक ही पाया गया। इससे स्पष्ट है कि 454/- रुपये का छलहरण हुआ है क्योंकि न लेखन सामग्री को प्राप्त ही किया गया है और न ही प्रयोग।

(3) प्राथमिक पाठशाला भवन लौहार लाहडी तथा खप्परनाला का कार्य मार्च 1987 को समाप्त हो गया था तो 31-3-87 को 30 बोरी तथा 20 बोरी तदनुसार कथ करने का क्या औचित्य था। इस प्रकार (1650 + 1100) मु0 2750/- रुपये का छलहरण किया गया है।

(4) प्रमाणक 6 दिनांक 10-6-85 के अनुसार संबंधी रूप लाल मिस्ट्री, अंग्रेज तथा बहादुर सिंह मजदूर के मास 4/85 के मस्ट्रोज संख्या 40 को रद्द करके मस्ट्रोज रजिस्टर संख्या 41 पर पुनः तैयार करके 2, 4 तथा 4 दिन तदनुसार बढ़ाकर मु0 120/- रुपये का छलहरण किया है।

(5) स्लेट के कथ पर डाला गया मास मार्च 89 में व्यय म0 1000/- रुपये संदिग्ध है क्योंकि प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर नहीं और न हों प्रधान द्वारा रसीद का सत्यापन ही किया गया है।

(6) रसीद संख्या 1 से 62 बुक न0 7 के अन्तर्गत गृहकर के जनवरी, 1987 में मु0 310/- रुपये प्राप्त किये परन्तु रोकड़ में इद्वाज जनवरी 1989 को किया गया अर्थात् दो वर्ष तक राशि का दुरुपयोग करते रहे हैं।

(7) वर्ष 1987 में किये गए लौहार लाहडी और खप्परनाला स्कूल के कार्यों पर किये गये खर्च के व्यय के दिनांक को रोकड़ में दर्ज करों नहीं किया गया। बिलम्ब से इद्वाज करना दुष्भावना का प्रतीक है।

(8) अंकेभण के समय स्टेट बैंक पटियाला, सहकारी सभा धीण की पास बुके प्रस्तुत न करने पर मु0 1120.11 तथा 1100/- रुपये की राशि की पुष्टि नहीं हो सकी। इससे स्पष्ट होता है कि तथ्यों को छुपाया जा रहा है।

(9) उपरनाला पाठशाला भवन में तीन खिड़कियों तथा एक दरवाजे के पल्ले नहीं लगाये गये हैं, फर्श नहीं किया गया है। इस प्रकार प्राथमिक पाठशाला भवन लौहार लाहडी में केवल दो दरवाजे के पल्ले लगाए गए हैं और खिड़कियों के पल्ले नहीं लगाये हैं।

(10) श्रीण स्कूल भवन निर्बाण में 1274.90 पैसे स्वीकृत अनुदान से अधिक व्यय किये गये हैं।

अतः मैं, बी0 के0 अग्रवाल, अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला श्री ज्ञान चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत चकवन्धीण, विकास खण्ड कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) तथा पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत कारण बताओ नॉटिस देता हूँ कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों का उत्तर इस पत्र की प्राप्ति के दस दिन के भीतर-भीतर अधिवक्ताकारी को प्राप्त हो जाना चाहिए। यदि विहित अवधि में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जाएगा कि आपको इस विषय में कुछ भी नहीं कहना है और विभाग आगामी आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

बी0 के0 अग्रवाल,
अतिरिक्त उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

खाय एवं श्रापूति विभाग, शिमला, जिला शिमला

अधिसूचना

शिमला-1, 22 जुलाई, 1991

संख्या सी0 सी0 एस0 11-15/77-6793-6873.—इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सी0 एस0 11-16/77-6077-6157, दिनांक 25-6-1991 की निरन्तरता में तथा हिमाचल प्रदेश जमावोरी एवं

मनाकाखोरी निरीधक आदेश, 1977 की धारा 3 (1) ई के 'प्रत्यांतं प्रदत्' ग्रन्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, पी० सी० ० कपूर, जिन दण्डाधिकारी, शिमला उपरोक्त आदेश की अनुसूची में इर्जं निम्नलिखित वस्तुओं के समस्त करों सहित अधिकतम परन्तु दरों का निवारण निम्न प्रकार ये करता हूँ :—

श्रावांक अनुसूची नं० के	वस्तु का नाम	समस्त करों सहित अधिकतम परन्तु दर	
1	2	3	4
4.	17.	पका खाना जो ढायीं व भोजनालयों में परोसा जाता है :	
	1. पूरा खाना दाल, सब्जी, चावल व चपाती सहित खुराक	8.00 ₹० प्रति बुराक	
	2. स्वीशल सब्जी, राजमाह, बन्दा, गोभी, शिमला मिठ्ठे, पालक, मटर	6.00 ₹० प्रति प्लेट	
	3. मटर पनीर, पालक पनीर	8.00 ₹० , "	
	4. चावल परमल	3.00 ₹० , "	
	5. चपाती तन्दूरी व दूसरी	0.75 ₹० , चपाती	
	6. बीट पका हुआ	12.00 ₹० प्लेट	
	7. चिकन करी	14.00 ₹० , "	
	8. दही रायता (200 ग्राम)	3.00 ₹० , "	
	9. दो पूरी सब्जी व दही के साथ	3.00 ₹० , "	
	10. दाल फाईड	3.00 ₹० , "	
	11. परांठा स्टफ़ड	1.50 ₹० , परांठा	
	मिठाई :		
	1. बर्फी, पिस्ता, कलाकन्द	38.00 ₹० प्रति किलो	
	2. बर्फी कोकोनेट	37.00 ₹० , "	
	3. सादी-बर्फी मिल्क केक	37.00 ₹० , "	
	4. लड्डू मोतीचूर	28.00 ₹० , "	
	5. लड्डू मोटा	24.00 ₹० , "	
	6. लड्डू बेसन व बेसन की बर्फी	26.00 ₹० , "	
	7. जलबी	24.00 ₹० , "	
	8. गुलाब जामुन पनीर की मिठाई	36.00 ₹० , "	
	9. बालुशाही, खुरपा, गाजर, मेहसु, पतीला, मूँगी दान, पिन्नी, अमरती	26.00 ₹० , "	
	10. सौन हल्दी	36.00 ₹० , "	
	11. मटर नमकोन, सेमियां, मुँगरा दान, भुजिया	26.00 ₹० , "	
	12. पकौड़ा	24.00 ₹० , "	
	13. समोसा प्रति पीस	1.00 ₹० प्रति पीस	
	14. चाय प्रति कप	1.00 ₹० प्रति कप	
5.	18.	दही :	
	1. दही	10.00 ₹० प्रति किलो	

दुकानदार को दुकान में सहज दृष्टिगत स्थान पर मल्य सची प्रदर्शित करनी होगी और उस पर दुकानदार/भागीदार/प्रबन्धक के हस्ताक्षर व लिंग का होमा अनिवार्य है।

यह आदेश हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने के पश्चात सारे शिमला जिला में एक माह की अवधि तक लाग रहेगा।

पी० सी० कपूर,
जिला दण्डाधिकारी, शिमला,
जिला शिमला।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4/30 जुलाई, 1991

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (५) १६/७६-१६.—अधिसूचना संख्या ३६-८२/७२ पंच-कांगड़ा, दिनांक ६ अक्टूबर, १९७२ को आंशिक रूप से संशोधित करके, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अन्तर्गत जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, १९६८ (वर्ष १९७० का १९७३ अधिनियम) की धारा ४ तथा ५ के अन्तर्गत प्राप्त हैं जिला कांगड़ा के विकास खण्ड नगरोटा बगवां की ग्राम सभा, सिद्धवाड़ी का पुनर्गठन निम्न प्रकार से करने के सहर्ष आदेश देते हैं:—

क्र० वर्तमान ग्राम सभा कोण्ठ संख्या २ संख्या २ कोण्ठ संख्या २ अपर्वाजित ग्रामों से बनी कोण्ठ सं० ५ विवरण सं० का नाम में वर्णित ग्राम में वर्णित ग्राम ग्राम सभा का नाम तथा में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के सभा से अपर्वाजित उसका मुख्यवास सभा में नाम होने वाले ग्रामों के नाम सम्मिलित होने बाले ग्रामों के नाम	१	२	३	४	५	६	७
---	---	---	---	---	---	---	---

विकास खण्ड नगरोटा: बगवां

१. सिद्धवाड़ी (सिद्धवाड़ी खास) ।	१. चकबन	—	सिद्धवाड़ी (सिद्धवाड़ी खास) ।	कोण्ठ सं० ३ में वर्णित सभी गांव तथा योल कैट से निकाले गए ग्राम १. ठेहड़ू	वर्णित ग्राम ग्राम सभी गांव तथा योल कैट से निकाले गए ग्राम १. ठेहड़ू और इन्हें निकट-वर्ती ग्राम सभा सिद्धवाड़ी में मिलाया जाना और इन्हें निकट-
	२. बाधनी				
	३. सिद्धवाड़ी खास ।				
	४. रकड़				
	५. रसी				

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

सचिव ।

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 4 जूलाई, 1991

संख्या पी० सी० ०३० एच०-एच० ७० (५) ३६/९१.—क्योंकि श्री बलवत्त मिह, निवासी गांव व डाकघर संधोट, जिला मण्डी की शिकायत पर प्रधान, ग्राम पंचायत संघोट, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी पंचायत निविव व शवन का कीमती सामान लकड़ी, स्लेट आदि को खुद-बुद्ध करने में मनिष्ठ पाए गए हैं।

यह कि इस मामले में विमान द्वारा प्रारम्भिक जांच करवाई गई तथा निम्न मुद्रे उभरे हैं:—

1. यह कि पंचायत घर का छत उद्धाड़ कर उसका जो सामान स्लेट $9 \times 18'' = 2450$ काटों = 30 पीपल (10×10) गज 170 पीपल (4×5) तथा मिलिंग पट्टी 122 कापल आदि की प्रधान पंचायत ने नीलामी की और 7069/- रुपये प्राप्त किए परन्तु न तो छत उद्धाड़ने की अनुमति ली और न ही नीलामी किए जाने की स्वीकृति एवं नीलामी सम्बन्धी रिकांड रखा जिसमें सामान खुद-बुद्ध करने को नाकारा नहीं जा सकता।

2. यह कि भवन की दिवारों की मुरम्मत करके बीम व स्लैब डाला गया जिसके लिए न तो तकनीकी विशेषज्ञ की राय ली गई और न ही स्लैब डालने से पहले सरिये, सीमेंट लगाने की तकनीकी सलाह ली गई। भवन की नींव भी पक्की नहीं की गई।

3. यह कि भवन ठेका श्री रोशन लाल पुत्र खजाना को मूँ 60,000 रुपये में बिना टैंडर बुलाये व तकनीकी सलाह लिए दिया गया जिसमें 52,000 हजार नकद देना था और 8,000/- रुपये का नीलामी का सामान। उस व्यक्ति को 2,600/- रुपये पेशगी जो बाद में वापिस लेकर 33,063-59 का सामान इंटे, रिट, बजारी क्रय किया गया तथा नीलामी का 7,069 रुपये का सामान भी दिया गया इसके लिए मूँ 25,000/- रुपये उपायुक्त से मुरम्मत के लिए स्वीकृत थे और 25,000/- जबाहर रोजगार योजना के अधीन खण्ड विकास अधिकारी से राशि ली गई जिसमें से मूँ 22,000/- रुपये रोशन लाल को पेशगी में दिए गये। इस बारे न कोई प्लान, एस्टीमेट बनाया गया न ही प्रशासकीय स्वीकृति लो गई और क्योंकि उपरोक्त मामले में वास्तविकता जानने के लिए नियमित जांच का करवाया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) के अधीन उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), सरकारी घट, जिला मण्डी को जहाँ जांच अधिकारी नियुक्त करने का आदेश देते हैं। वह अपनी जांच रिपोर्ट उपायुक्त, मण्डी के माध्यम से शीघ्र प्रस्तुत करेंगे। वह अधीक्षक ग्रेड-2 कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, धर्मपुर (मण्डी) को प्रस्तुत कर्ता नियुक्त करते हैं जो जांच के दौरान सरकार का पक्ष भी प्रस्तुत करेंगे।

हस्ताक्षरित/
मंचर सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।